खबर संक्षेप

नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री यादव 6 मई को ग्रहण करेंगे पदभार

भोपाल। मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के नव नियुक्त अध्यक्ष डॉ. कृष्णापाल सिंह यादव और उपाध्यक्ष श्री संजीव कांकर 6 मई को दोपहर 1:30 बजे निगम के कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे। बिजली कार्मिक स्थानान्तरण के लिये करें ऑनलाइन आवेदन

19 मई 2026 तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कर्मचारियों (नियमित/संविदा) के सेवा संबंधी मामलों में विस्तार करते हुए कार्मिकों के स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण की सुविधा को और अधिक सरल बनाते हुए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई है। कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं लाइन स्टॉफ को स्वयं अथवा परिवार में किसी सदस्य की गंभीर बीमारी, पति/पत्नी के शासकीय सेवा में अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होने पर/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में कार्यरत होने पर, आपसी स्थानान्तरण तथा अन्य कारणों से उनके स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण के लिये ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की है। उप महाप्रबंधक स्तर तक के अधिकारी/कर्मचारी स्थानांतरण के लिये ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे एवं ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनकी एक ही स्थान पर पदस्थापना की अवधि 01 वर्ष से कम है उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का पुनर्गठन

भोपाल। राष्ट्रीय हरित अधिकरण मुख्य बेंच, नई दिल्ली द्वारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का पुनर्गठन किया है। समिति में अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, परिवहन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, प्रमुख सचिव राजस्व, वन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, खनिज संसाधन, पशुपालन एवं डेयरी, सूक्ष्म, लघू और मध्यम उद्यम, प्रमुख सचिव/सचिव स्कूल शिक्षा, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल, आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल, सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, संचालक पर्यावरण नियोजन एवं समन्वयक संगठन (ई.पी.सी.ओ) भोपाल, मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान भोपाल, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल, क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय रिजर्व बैंक सदस्य होंगे। मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल और मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), म.प्र. भोपाल को सदस्य-सचिव नामित किया गया है।

श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह में आधुनिक रेलवे प्लेटफॉर्म का शुभारंभ

भोपाल। मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह दोंगलिया में फ्लाई ऐश के कुशल प्रबंधन एवं परिवहन के लिए एक आधुनिक रेलवे प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी पीएम गतिशक्ति परियोजना के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य देश में लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को सुदृढ़ करना और परिवहन को अधिक प्रभावी बनाना है।

कृषक कल्याण वर्ष-2026: भावांतर से लेकर यंत्रीकरण तक, हर कदम पर किसानों की आय बढ़ाना और खेती की लागत घटाना ही हमारा संकल्प : मुख्यमंत्री

- 2868 करोड़ से कृषि यंत्रीकरण को मिल रहा है बढ़ावा
- देश के सर्वाधिक 5629 कस्टम हायरिंग केंद्र प्रदेश में स्थापित
- सोयाबीन में 1476 करोड़ का भावांतर, श्रीअन्न पर 1000 रुपये बोनस से बदलेगी खेती

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 'कृषक कल्याण वर्ष 2026' में कृषि विभाग ने अन्नदाता को अन्न से लेकर आय तक, परंपरा से लेकर तकनीक तक, हर मोर्चे पर सशक्त किया है। समर्थन मूल्य, भावांतर, श्रीअन्न प्रोत्साहन, भंडारण, डिजिटल व्यवस्था और कृषि यंत्रीकरण से प्रदेश का किसान अब लागत घटाकर, आय बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।

राज्य शासन ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं खरीदी के लिये स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई 2026 तक कर दी है और प्रदेशभर में गेहूं का उपार्जन जारी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में चना एवं मसूर का उपार्जन 30 मार्च से 28 मई 2026 तक किया जा रहा है। उड़द प्रोत्साहन योजना वर्ष 2026 में राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। इससे ग्रीष्मकालीन उड़द

का रकबा बढ़ेगा।

भावांतर भुगतान योजना में 7.10 लाख पंजीकृत किसानों द्वारा 16.95 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का विक्रय किया गया। समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर की 1476 करोड़ रुपये की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से सीधे किसानों के खातों में अंतरित की गई। सरसों में 1.5 लाख किसान पंजीकृत हैं और योजना संचालित है।

रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में 1 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक प्रमुख उत्पादक 15 जिलों के 3,894 किसानों से 2,829.92 मीट्रिक टन कोदो-कुटकी का उपार्जन किया गया। राज्य सरकार द्वारा क्रय मूल्य के अतिरिक्त 1000 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से किसानों को दी जाएगी। इससे श्रीअन्न की मूल्य श्रृंखला विकसित होगी और किसानों की आय बढ़ेगी।

किसानों की उपज सुरक्षित रखने के लिए खाद्यान्न भंडारण योजना के तहत 3.55 लाख मीट्रिक टन नई भंडारण क्षमता निर्मित की जा चुकी हैं। भंडार योजना-सामग्री में 15 लाख मीट्रिक टन क्षमता के आधुनिक गोदाम बनाए जा रहे हैं, जिनमें 11 लाख मीट्रिक टन का पंजीयन पूरा हो गया है। किसानों को बेहतर दाम दिलाने के लिए 50 कृषि उपज मंडियों में ग्रेडिंग-सॉर्टिंग एवं पैकेजिंग संयंत्र की स्थापना की जा रही है। किसान अपनी उपज की ग्रेडिंग-सॉर्टिंग तथा पैकेजिंग निःशुल्क करा सकेंगे, जिससे मूल्य संवर्धन होगा।

ई-विकास प्रणाली के जरिए किसानों को सुगमतापूर्वक उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। इस डिजिटल व्यवस्था से लंबी कतारें, कालाबाजारी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। 01 अप्रैल 2026 से सभी जिलों में ई-किसान प्रणाली लागू है। किसान रजिस्ट्री से हर किसान को विशिष्ट पहचान और खेत की रजिस्ट्री से हर खेत की जियो-टैगिंग की जा रही है, जिससे फसल बीमा, ड्रोन छिड़काव और नुकसान का आंकलन आसान हुआ है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 3 लाख एकड़ में जैविक-प्राकृतिक खेती कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश के 56 कृषि विज्ञान केंद्र तकनीकी सहायता दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती के लिये एक हजार से अधिक जैव संसाधन केंद्र और तीन हजार से अधिक कृषि सखी कार्यरत हैं। 200 से अधिक कृषि वैज्ञानिकों को संसाधन व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।

विक्रमोत्सव : 2026 को कल्चरल लाइव इवेंट ऑफ द ईयर में गोल्ड और शासकीय सहभागिता में मिला सिल्वर अवॉर्ड

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को डब्ल्यूओडब्ल्यू लाईव अवार्डस की टीम भोपाल आकर विक्रमोत्सव 2026 को इस वर्ष मिले गोल्ड और सिल्वर अवार्ड प्रदान करेंगी। नई दिल्ली में 1 और 2 मई 2026 को आयोजित शोज ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव 2026 में विक्रमोत्सव 2026 को कल्चरल लाइव इवेंट ऑफ द ईयर में गोल्ड अवॉर्ड तथा लाइव इवेंट में सर्वश्रेष्ठ शासकीय सहभागिता की श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ।

यह पुरस्कार डब्ल्यूओडब्लयू लाईव अवॉर्ड्स के अंतर्गत प्रदान किए गए, जो देश में कॉन्सर्ट, फेस्टिवल, टूर और लाइव इवेंट्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रचनाकारों और दूरदर्शियों को सम्मानित करते हैं। इस वर्ष 300 से अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई, जो इस क्षेत्र के बढ़ते विस्तार, विविधता और संभावनाओं को दर्शाती हैं। विशेषज्ञ जूरी पैनल द्वारा इन प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया गया।

मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार एवं महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्री श्रीराम तिवारी ने बताया कि विक्रमोत्सव : 2026 को मिले गोल्ड एवं सिल्वर अवॉर्ड मध्यप्रदेश के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। यह सम्मान न केवल मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह मध्यप्रदेश की पारंपरिक एवं आधुनिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विरासत से विकास के मंत्र अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश निरंतर कार्य कर रहा है। मध्यप्रदेश सरकार निरंतर ऐसे आयोजनों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सशक्त और समृद्ध बनाने का कार्य कर रही है। विक्रमोत्सव हमारी परंपराओं, मूल्यों और नवाचार का जीवंत उत्सव बन गया है। यह उपलब्धि हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी तथा भविष्य में मध्यप्रदेश को सांस्कृतिक क्षेत्र में नई ऊँचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

विगत वर्षों में मिल चुके है तीन सम्मानः विक्रमोत्सव दुनिया का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला सांस्कृतिक आयोजन है। इसमें सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ बिजनेस इवेंट भी शामिल है। इसके पहले विक्रमोत्सव : 2025 को ईमैक्स ग्लोबल अवार्ड द्वारा लांगस्टैंडिंग आईपी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था।

8.12 लाख किसानों से 44.16 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का हुआ उपार्जन : खाद्य मंत्री श्री राजपूत

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि अभी तक 8 लाख 12 हजार किसानों से 44 लाख 16 हजार मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी की जा चुकी है। उन्होंने बताया है की तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 तक कर दिया गया है। गेहूँ का उपार्जन सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक किया जाता है।

मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि अभी तक 14 लाख 78 हजार किसानों द्वारा गेहूँ उपार्जन के लिए स्लॉट बुक कराए गए हैं। किसानों के हित में गेहूँ उपार्जन की अवधि 9 मई

से बढ़ाकर 23 मई 2026 तक की गई। प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर तौल कांटों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 की गई तथा तौल कांटों की संख्या में वृद्धि का अधिकार जिलों को दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही एनआईसी सर्वर की क्षमता एवं संख्या में वृद्धि कराई गई। खाद्य विभाग द्वारा प्रति घंटा स्लॉट बुकिंग एवं उपार्जन की मॉनिटरिंग की जा रही है।

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि किसानों को 7383.01 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उपार्जन केन्द्र पर किसानों की सुविधा के लिए पीने का पानी, बैठने के लिए छायादार स्थान, जन सुविधाए आदि की व्यवस्थाएँ की गई हैं।

किसानों के उपज की तौल समय पर हो सके, इस हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं। इसमें बारदाने, तौल कांटे, हम्माल तुलावटी, सिलाई मशीन, कम्प्यूटर, नेट कनेक्शन, गुणवत्ता परीक्षण उपकरण, उपज की साफ सफाई के लिए पंखा, छन्ना आदि की व्यवस्था की गई है। उपार्जन केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं के फोटो ग्राफ्स भारत सरकार के खरीद केंद्र स्व-मूल्यांकन पोर्टल पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही की जा रही है।

किसानों से 2585 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस राशि सहित 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ का उपार्जन किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये आवश्यक बारदानों की व्यवस्था की जा चुकी है। उपार्जित गेहूँ की भर्ती जूट बारदाने के साथ साथ पीपी/एचडीपी बेग एवं जूट के एक भर्ती बारदाने का उपयोग किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था की गई, जिससे उपार्जित गेहूँ का सुरक्षित भण्डारण किया जा सके।

इंदौर में 9 से 13 जून तक होगा ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गर्व का विषय है कि ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 9 से 13 जून तक इंदौर में होने जा रहा है। विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के इस समूह को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है। सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार और भू-राजनीतिक संवाद को बढ़ाना ब्रिक्स आंदोलन का उद्देश्य है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, मिस्त्र, सऊदी अरब, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड ,संयुक्त अरब अमीरात, कोलंबिया, इंडोनेशिया आदि 21 देश के मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्धारक आदि भी सहभागिता करेंगे। यह 5 दिवसीय सम्मेलन पूर्ण गरिमा और गौरव के साथ हो, यह राज्य सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह जानकारी, मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में दी।

नगरीय निकायों को पीपीपी मोड पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के

लिए किया जाएगा प्रोत्साहित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि खरगोन के जलूद में मेगा सोलर पॉवर प्लांट का लोकार्पण किया गया है। पीपीपी मोड पर 271 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित 60 मेगावाट क्षमता का यह पावर प्लांट नगर निगम इंदौर द्वारा ग्रीन बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत लगाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि जन भागीदारी से संचालित इस योजना में एक-एक लाख रुपए तक के 10 बॉन्ड तक लेने की अनुमति थी। इस पर वार्षिक 8.27 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। परियोजना की लागत 8 साल में प्राप्त हो जाएगी, यह परियोजना 20 साल तक कार्यरत रहेगी। इससे लगभग 35 से 60 करोड़ रुपए तक की बचत नगर निगम इंदौर को होगी। इस परियोजना से जन भागीदारी के माध्यम से आय प्राप्त करने के अवसर भी जन सामान्य को प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रीगण को अपने-अपने प्रभार के जिलों में नगरीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा आधारित इस प्रकार की परियोजनाओं की स्थापना और संचालन को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

जिला विकास समितियों की बैठक का आयोजन 12 मई से पहले करें सुनिश्चित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार का ढाई वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। दिनांक 8 से 10 मई के बीच विभागवार मंत्रीगण और विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा का कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है। इसमें मंत्री गण अपने विभाग और अपने प्रभार के जिले की उपलब्धियां, नवाचार, आगे की कार्य योजना और चुनौतियों के बारे में जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि जिला विकास समितियों की बैठक 12 मई के पहले प्रभार के जिले में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न निगम/मंडलों में अशासकीय नियुक्तियां एवं नामांकन किए गए हैं। अपने-अपने विभाग में मंत्रीगण इन सभी का मार्गदर्शन एवं उन्मुखीकरण करें। राज्य स्तर पर भी इन सभी का एक दिवसीय उन्मुखीकरण आयोजित किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि भोपाल में 30 अप्रैल को किसानों के सशक्तिकरण और उनकी आय वृद्धि के उद्देश्य से कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला के सभी 55 जिले, विकासखंड, क्लस्टर लेवल और ग्राम पंचायतों से कृषि से जुड़े 16 विभागों के 1627 चुनिंदा अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गेहूँ उपार्जन के संबंध में बताया कि 19 लाख किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। उपार्जन की अद्यतन स्थिति 41 लाख मीट्रिक टन है, जिसके लिए 6520 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। अब तक 14.70 लाख स्लाट बुकिंग कृषकों द्वारा की गई है। विक्रेता कृषकों की संख्या 7 लाख 77 हजार है।

आगर मालवा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए की प्रभावी कार्रवाई

- 4 क्विंटल से अधिक डोडाचूरा जब्त, 02 आरोपी गिरफ्तार
- 45 लाख 57 हजार रूपए से अधिक की संपत्ति जब्त

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशभर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध लगातार कार्यवाहियां की जा रही हैं। इसी कार्यवाही के दौरान आगर मालवा जिले की बड़ौद पुलिस ने 4 क्विंटल से अधिक का अवैध डोडाचूरा एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन सहित लगभग 45 लाख 57 हजार रूपए की संपत्ति जब्त की है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

04 मई को थाना बड़ौद पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली कि डग-बड़ौद मार्ग पर एक ट्रक में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा को ग्लूकोज कार्टूनों के बीच छिपाकर परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर त्वरित एवं योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने खंदवास जोड़, ग्राम बंदवास क्षेत्र में घेराबंदी कर उक्त वाहन को रोका।

तलाशी के दौरान ट्रक में रखे ग्लूकोज कार्टूनों के बीच छिपाकर रखी गई 20 प्लास्टिक बोरियों से कुल 4 क्विंटल 3 किलो 353 ग्राम अवैध डोडाचूरा जब्?त किया गया। मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से डोडाचूरा, परिवहन में प्रयुक्त ट्रक एवं अन्य सामग्री सहित लगभग 45 लाख 57 हजार रुपए से अधिक की संपत्ति जप्त की है। आरोपी से पूछताछ के आधार पर उज्जैन निवासी सह-आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है तथा मादक पदार्थ के स्रोत एवं तस्करी नेटवर्क के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई निरंतर जारी है तथा इस प्रकार के अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है।

मुरैना के डायल-112 हीरोज
ई-रिक्शा एवं मोटर साइकिल की टक्कर में घायल हुए 03 व्यक्तियों को पहुँचाया अस्पताल

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुरैना जिले के थाना जौरा क्षेत्र में डायल-112 जवानों की तत्पर एवं संवेदनशील कार्रवाई से ई-रिक्शा एवं मोटर साइकिल की टक्कर में गंभीर रूप से घायल तीन व्यक्तियों को समय पर अस्पताल पहुँचाकर उपचार उपलब्ध कराया गया। इस त्वरित कार्रवाई से घायलों को शीघ्र चिकित्सकीय सहायता मिल सकी।

05 मई को राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112, भोपाल को सूचना प्राप्त हुई कि थाना जौरा क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास ई-रिक्शा एवं मोटर साइकिल की टक्कर में 03 व्यक्ति घायल हो गए हैं। तत्काल पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सूचना प्राप्त होते ही जौरा थाना क्षेत्र में तैनात डायल-112 एफआरव्ही वाहन को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।

मौके पर पहुँचकर डायल-112 स्टाफ आरक्षक श्री मेघराज नारायण एवं पायलट श्री मनोज धाकड़ ने पाया कि ई-रिक्शा एवं मोटर साइकिल दुर्घटना में 03 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। डायल-112 जवानों ने सभी

घायलों को तत्काल एफआरव्ही वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जौरा पहुँचाया। डायल-112 जवानों की त्वरित एवं समर्पित कार्यवाही से घायलों को समय पर उपचार उपलब्ध हो सका। डायल-112 हीरोज श्रृंखला के अंतर्गत यह घटना दर्शाती है कि मध्यप्रदेश पुलिस की डायल-112 सेवा आपात परिस्थितियों में आमजन की सहायता हेतु सदैव सजग, संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है।

केरवा डैम के क्षतिग्रस्त वेस्टवियर का कार्य आगामी दो माह में पूर्ण करें : मंत्री श्री सिलावट

- वेस्टवियर पुनर्निर्माण कार्य का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने निर्देश दिए हैं कि केरवा डैम के क्षतिग्रस्त वेस्टवियर का कार्य आगामी दो माह में पूर्ण किया जाए। कार्य पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक हो एवं संबंधित अधिकारी निरंतर कार्य का निरीक्षण कर वरिष्ठ अधिकारियों को प्रगति की जानकारी दें। कुछ माह पूर्व बांध के वेस्टवियर का स्लैब अत्यधिक पुराना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका वर्तमान में पुनः निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने मंगलवार को केरवा बांध के क्षतिग्रस्त वेस्टवियर के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और

कार्य के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधीक्षण यंत्री श्री बी.एल. निमामा, कार्यपालन यंत्री श्री नितिन कुहिकर, अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रदीप चतुर्वेदी तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

केरवा बांध की कुल लंबाई 396. 50 मीटर एवं उंचाई 22.6 मीटर है। बांध की कुल जीवित जल भराव क्षमता 22.6 मिलियन घन मीटर है, जिससे भोपाल जिले के लगभग 35 ग्रामों की 3 हजार 960 हेक्टेयर भूमि में रबी सिंचाई किया जाना रूपांकित है। इसके अतिरिक्त जलाशय से पेयजल के लिए जल भी प्रदाय किया जाता है। स्थल निरीक्षण के दौरान मैदानी अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि टूटे हुए हिस्से को डिस्मेंटल कर नवीन निर्माण के लिए फाउंडेशन लेवल तक खुदाई का कार्य किया जा चुका है।

उपेक्षा से आक्रोशित साहू समाजः प्रतिनिधित्व न मिलने पर भाजपा अध्यक्ष से सीधी बात

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मध्यप्रदेश में भाजपा शासन द्वारा विभिन्न निगम/ मंडलों/ आयोग/ परिषदों एवं अकादमियों में नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है। तथापि, इन में अब तक साहू समाज को अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। फल स्वरुप समाज में असंतोष की भावना परिलक्षित हो रही है। इसी संदर्भ में मध्यप्रदेश सर्व साहू समाज का एक प्रतिनिधिमंडल श्री ओमप्रकाश साहू के नेतृत्व में, हेमंत खंडेलवाल से भेंट करने पहुँचा। प्रतिनिधिमंडल ने उनसे आग्रह किया कि निगम-मंडलों में होने वाली नियुक्तियों में साहू समाज के योग्य एवं समर्पित कार्यकर्ताओं अथवा पदाधिकारियों को समुचित अवसर प्रदान किया जाए। इस संबंध में एक औपचारिक ज्ञापन भी सौंपा गया।

प्रतिनिधिमंडल में प्रांतीयजन सर्व श्री अनिल कुमार साहू, श्री हरिशंकर साहू, श्री मदनलाल साहू, डॉ. एच.एल. साहू, श्री मोहनलाल मोदी तथा गुना से डॉ. बृजेश कुमार साहू सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी नेतृत्व समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगा।